immense visa problems all over the country. I would like to ask the hon. Minister—we had discussed this earlier also--whether there is any proposal to ease out the situation to have visa on arrival.

SHRI E. AHAMMED: Sir, this matter is under consideration. I will not be able to say that a decision has been taken. That is also one of the proposals. But, every time when we discuss about issuing of visas, security concerns should also be taken into account. And, hon. Member, Shri Shahid Siddiqui, also mentioned about Islamabad, but it will be taken up only in a reciprocal manner. We must also have the local Government's assistance and permission. So, easing out the process of issuing visas for the tourists is also under consideration to promote tourism in this country.

पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं में खेल क्षमता

*265. श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों के बालक तथा बालिकाओं में अच्छा खिलाड़ी बनने की क्षमता मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में खेल क्षमता का विकास करने के लिए वहां एक खेल अकादमी स्थापित करने संबंधी कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बालक और बालिकाओं में अच्छे खिलाड़ियों के बनने की क्षमता असंदिग्ध है।

(ख) और (ग) राज्य खेल अकादमियों के प्रायोजकों के लिए अनुदान देने की भारत सरकार की एक योजना है। योजना का प्रमुख लक्ष्य 10 से 13 वर्ष के आयु समूह में खेलों में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, 10 से 18 वर्ष के आयु समूह में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चोटी का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन तथा आगामी वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने के लिए उन्हें तैयार तथा विकसित करना है।

योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन तथा एक प्रायोजक के संयुक्त वित्त-पोषण से एक सहयोगी उपक्रम के रूप में राज्य खेल अकादमियों के गठन की परिकल्पना की गई है। 8.30 करोड़ रुपये की उच्चतर सीमा के साथ पूंजी, गैर-आवर्ती लागतों के संबंध में अकादमी को वित्तीय सहायता प्रायोजक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य हिस्सेदारी का अनुपात 51:25:24 होता है। इसके अलावा, प्रतिवर्ष 17.00 लाख रुपये तक की आवर्ती लागत या वास्तविक व्यय का 25%, जो भी कम हो, भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिदेय होगा।

योजना के तहत अनुदान केवल निम्नलिखित प्रायोजकों को दिए जा सकते हैं:-

1. सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रम

2. अलग-अलग प्रायोजक

3. गैर-सरकारी संगठन

अनुदान केवल राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन की सिफारिश पर जारी किए जाते हैं।

कोई भी प्रायोजक सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन के माध्यम से किसी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में खेल अकादमी के गठन के लिए आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन अकादमी के लिए शहरी क्षेत्र में कम से कम 10 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ नि:शुल्क भूखंड प्रमाणित करेगा।

(घ) खेद है कि अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य खेल अकादमी के गठन के लिए किसी भी प्रायोजक से कोई व्यावहारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Sports Potential Amongst Youth of NER

†*265. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the boys and girls of the North-Eastern States have the potential to become a good sportsperson;

(b) if so, whether there is any scheme under the consideration to establish a sports academy in that region with a view to exploit the sports potential;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

† Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir, there is no doubt that the boys and girls of the North-Eastern States have the potential to become good sportspersons.

(b) and (c) The Government of India have a Scheme for giving grants to sponsors of State Sports Academies. The main objective of the Scheme is to select the best available talent in sports in the age group 10—13 years, as well as top performers in State/National competitions in the age group 10—18 years, and to prepare and groom them over the years for winning medals for the country at the international level.

The Scheme envisages setting up State Sports Academies as a co-operative venture with joint funding by the Central Government, State Government/UT Administration and a Sponsor. The financial assistance to the Academy in respect of capital, non-recurring costs with an upper cap of Rs. 8.30 crore is to be shared between the Sponsor, the Central Government and the State Government in the ratio of 51:25:24. In addition, recurring cost up to Rs. 17.00 lakh per annum or 25% of actual expenditure, which ever is less, is payable for a period of three years by the Government of India.

Grants under the Scheme can be availed of only by the following sponsors:

(i) Public/Private Sector Undertakings

(ii) Individual sponsors

(iii) NGOs

Grants are released only on the recommendation of the State Government/UT Administration.

A sponsor can apply for setting up a Sports Academy in a State/UT through the State Government/UT Administration accompanied by all required documents. The availability of land for the Academy of a minimum of 10 acres in an urban area and about 20 acres in rural areas free of cost, will be certified by the State Government/UT Administration.

(d) Regrettably, so far no viable proposal has been received from any sponsor for setting up a State Sports Academy in the North-East Region.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मुझे मंत्री जी का उत्तर पढ़कर काफी निराशा हुई है क्योंकि उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर के बालक-बालिकाओं में अच्छे खिलाड़ी बनने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन उन्होंने कहा कि खेद है कि स्पोर्ट्स अकादमी का कोई व्यावहारिक प्रस्ताव किसी राज्य से नहीं आया है। इसलिए वहां स्पोर्ट्स अकादमी बनाने का कोई प्रस्ताव उन के विचाराधीन नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य अन्य राज्यों जैसे नहीं हैं और उन की विशेष परिस्थिति को देखते हुए एक अलग मंत्रालय ''डोनर'' बनाया गया है और एक नॉन-लैप्सेबल पूल ऑफ रिसोर्सेस भी उन के लिए रखा गया है। इसलिए वहां व्यावहारिक प्रस्ताव किसी अन्य प्रायोजक से आने के बजाय क्या आप ''डोनर'' से बात कर के इस तरह का कोई प्रस्ताव लाएंगे ताकि उन बच्चों की जो क्षमता है, उस का दोहन किया जा सके और वहां एक स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जा सके?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं मानता हूं कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र एक खास क्षेत्र है जहां हमें खास ध्यान देना चाहिए, लेकिन चूंकि सवाल स्टेट्स अकादमी के बारे में था, इस के लिए एक परियोजना तैयार की गयी है। उस के अंतर्गत न केवल पूर्वोत्तर से बल्कि कहीं से भी सही प्रस्ताव हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए उस पूरी परियोजना पर पुन:विचार चल रहा है। जहां तक स्पोर्ट्स अकादमी का सवाल है, मणिपुर में एक अकादमी बनायी गयी है जब कि वहां कुछ साल पहले नेशनल स्पोर्ट्स हुए थे। उस को सही बनाने के लिए, उस को और बेहतर बनाने के लिए मणिपुर सरकार की तरफ से मांग आई थी कि हम उन को एक खास मदद दें और जब 20-21 नवंबर, 2004 को प्रधान मंत्री महोदय वहां गए थे, तब इस विषय पर यह तय किया गया था, जिसे मैं पढ़कर सुनाने वाला हूं, कि इस पर हम यहां दिल्ली में सोच-विचार करेंगे। It is "Establishing a Sports Academy at Khuman Lampak, including one-time maintenance and repairs at existing facilities". इस पर विचार हुआ है और यह तय किया गया है कि ''डोनर'' के जो नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस हैं, उस में से जो कैपिटल कॉस्ट्स हैं, उन के लिए हम कुछ मदद दे सकते हैं और इस पर भी कुछ चर्चा हुई है कि कितनी मदद दी जा सकती है। उस के लिए कोई 14 करोड़ की बात चल रही है, लेकिन क्योंकि इस पूल से पैसा लेने के लिए प्राथमिकताएं उन्हीं राज्यों को बतानी है, उन से मांग की गयी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं हमारे पास पहुंचाएं ताकि यदि उस में इस अकादमी की बात हो और वह सही जगह पर हो तब हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। वह लिस्ट हमें अभी-अभी मिली है, मुझे नहीं लेकिन ''डोनर'' को मिली है, जिस पर वह विचार कर रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि

कम-से-कम यहां हम आने वाले कुछ हफ्तों में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। महोदय, पूर्वोत्तर के लिए और बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे खुशी है कि वहां के कोई 1500 नौजवान लड़के-लड़कियों को स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया गया है और हमारी जो 'खुसूसन इंस्टीटयूट्स हैं, वहां एक नेता जी सुभाष इंस्टीटयूट है, जोकि इम्फाल में तकियाल में है, उस को भी बेहतर बनाने पर विचार चल रहा है मदोदय, एक खास नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स फेस्टीवल हर साल आयोजित किया जाता है। उस पर भी हम खास ध्यान देते हैं। ये सब इनीशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उस के अंतर्गत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इम्फाल में एक रीजनल सेंटर व एक सब-सेंटर गोहाटी में बनाया है। इम्फाल और आइजाल में कुछ खास खेल ऐसे हैं, जो कि पूर्वोत्तर में खेले जाते हैं, मिसाल के तौर पर Judo, boxing, wrestling, weight lifting, karate और taekwandoo. इनके लिए वहां खास सहूलियतें उपलब्ध कराए गए हैं। यह archery के लिए भी किया गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हम करते रहेंगे, ...(व्यवधान).... लेकिन वह जो पुरानी परियोजना थी, जिसके प्रति हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उस पर पुनर्विचार हो रहा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हम नई परियोजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर में कुछ कर पाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मंत्री महोदय ने काफी विस्तृत जानकारी, जो सवाल से आगे भी जा कर थी, वह दे दी है। मैं उनको बताना चाहती हूं और शायद उन्हें जानकारी भी होगी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए एक 'विज़न 2020' तैयार किया जा रहा है। जब हम किसी भी क्षेत्र के लिए कोई विज़न तैयार करते हैं, तो उसका बेसिस यह होता है कि हम वहां के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेज़ को आइडेंटिफाई करके वीकनेसेज़ को दूर करने का और स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा स्ट्रांग करने की बात करें। जैसा आपने भी स्वीकार किया है कि जब हम पूर्वोत्तर के राज्यों की स्ट्रेंथ्स देखते हैं, तो खेल-क्षमता वहां की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में उभर कर आती है।

आपने मणिपुर का जिक्र किया कि मणिपुर में खेल हुए थे। इस बार गोवाहाटी में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। अगर आप इन दोनों जगहों को जाकर देखें, तो पाएंगे कि वहां बहुत बड़ा infrastructure मौजूद है। इसलिए जब हम स्पोर्ट्स एकैडमी की बात करते हैं, तो 10 एकड़ जमीन की तो कोई बात ही नहीं है आप उन्हीं दोनों में से किसी एक को कंवर्ट कर सकते हैं। वहां के उस infrastructure को यूज़ करिए। वहां बहुत बड़ा infrastructure है – रहने का, खेलने का, ऑडोटोरियम्स, स्टेडियम्स। ये सब सैंकड़ों-सैंकड़ों करोड़ रुपए लगाकर बने हुए हैं। उन्हीं दोनों में से किसी एक को राज्य सरकार का इंतजार न करते हुए, वहां एक दूसरी विकास संस्था एन्ई्सी है, अगर डोनर को यह लगता है कि राज्य की ही प्राथमिकता आएगी, तो एन्ई्सी के माध्यम से क्या आप स्पोर्ट्स एकैडमी का एक प्रस्ताव लेकर किसी को कन्वर्ट करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर: सर, मुझे खेद है कि पूर्व सरकार ने एक ऐसी परियोजना तैयार की, जिसके अन्तर्गत हम न केवल पूर्वोत्तर में बल्कि भारतवर्ष में कहीं भी स्टेट्स स्पोर्ट्स एकैडमी स्थापित नहीं कर पाए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: तो आप जाकर कीजिए न!

श्री मणि शंकर अय्यर: अब हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। जब वह दुरुस्त कर लिया जाएगा, तब मेरे ख्याल में जो दिक्कतें हमने पिछले कुछ महीनों में महसूस की हैं, उनको सही करने के बाद मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है कि वहां स्टेट्स स्पोर्ट्स एकैडमी हम शुरू कर पाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर: लेकिन, जब तक स्पोंसर न आए, तब तक दिक्कत होगी। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: एन०ई०सी० को स्पोंसर बनाइए न! ...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर: और वह स्पोंसर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: एन०ई०सी० भी हो सकता है न! ...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं सुषमा जी से अनुरोध करता हूं कि वे बड़ी-बड़ी तेल कम्पनियों के पास जाएं और उनसे कहें कि वे आकर स्पोंसरशिप दें, तभी जाकर किया जा सकता है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं क्यों जाऊं, आप पूर्व मंत्री हैं। ...(व्यवधान)... आप जाइए न! ...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर: क्योंकि मैं अब मंत्री नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जा सकता हूं। ...(व्यवधान)... आपसे मेरा अनुरोध है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप पूर्व मंत्री हैं, तेल कम्पनियां आपकी सुनेंगी, वे मेरी क्या सुनेंगी? ...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं तो पूर्व हूं, आप तो मौजूद हैं। ...(व्यवधान)... इसलिए आप जाकर पूछिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप प्रभाव का इस्तेमाल करिए न! ...(व्यवधान)...

MR CHAIRMAN: Next Shri Dwijendra Nath Sharmah. ...(व्यवधान)...

डा॰ कुमकुम राय: सर, 268 भी इससे जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, the hon. Minister has given a detailed reply to this question. But, Sushmaji is very correct that with this ratio of 51: 25:24, it will be impossible to get new sponsors to open Sports Academies, particularly in the North East Region. The hon. Minister has said that some stadiums and other facilities are coming up there because of the National Games, which will be held next year. But if you look at the district level...

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: I am putting my question, Sir. There are a lot of proposals lying with the Ministry, either the Sports Ministry or DONER, regarding stadiums and other sports facilities at the district level, particularly in Assam. May I know from the hon. Minister how many such proposals are lying with the Government?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, we have had from the 1st of April, 2005, what used to be a Centrally-sponsored scheme of providing sports infrastructure in the State, and in the district and sub-district levels, which has been transferred to the State sector. This being so, it is only the approved schemes where we are able to help in completing the commitments. But, with regard to anything new, I am afraid, we have, at the present moment, to go to the State Government. Their resources have been substantially augmented as a result of the Twelfth Finance Commission and the action taken on it by the Ministry of Finance. But, I do believe that we do need to look at the possibility of assisting the States in this sector. I am thinking about it at the moment. But, as of now, there is no scheme under which we can assist sports at the district and sub-district level in any State, including Assam.

SHRI T.R. ZELIANG: North-Eastern region is one area, from where the country has discovered talented boys and girls. so, if the Government has to pay special attention, I think this system of 10 per cent, or 20 per cent, grant has to be done away with; hundred per cent grant should be given to imporve sports infrastructure. Now, as per the new guidelines,

the sports infrastructure development will be done by the States. I may cite one example. In Nagaland, it took them 15 years to complete Indira Gandhi Stadium. So, this can be done only by the State and the Central assistance. So, where we need to pay special attention to sports infrastructure, that would be possible only by hundred per cent grant from Central Government. Can Central Government restore old system and grant hunded per cent assistance to improve sports infrastructure?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I have noted his suggestion.

श्री राम नारायण साहू: माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा देश के कौन-कौन से राज्य या क्षेत्र खेल पोटेंशियल हेतु चिन्हित किए गए हैं? और, क्या उनमें उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र सम्मिलित है?

श्री मणि शंकर अय्यर: सभापति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के हर कोने में हमें ऐसे लड़के-लड़कियां मिल सकते हैं, जो कि देश की शान बढ़ा सकें और उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। हमारे जो कार्यक्रम हैं, वे उत्तर प्रदेश राज्य में भी चलते आ रहे हैं और यदि इस सिलसिले में माननीय सदस्य के कुछ खास सुझाव हों, तो उनकी अपेक्षा में मैं बैठा हूं।

Telecast of Achievements in S&T

*266. SHRI DARA SINGH:

SHRI ABU ASIM AZMI:††

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether his ministry has tied up with National Geographic Channel to produce and telecast a range of programmes showing the achievements made in different disciplines of science and technology in India;

(b) if so, the details thereof;

(c) the length of films proposed to be produced;

(d) the expenditure likely to be incurred thereon; and

(e) the time by which the said films are likely to be telecast?

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): (a) and (b) Yes Sir. The basic purpose of the proposed year-long campaign is to educate and inform the general public about the great work done by national research and development institutes and laboratories across India by showcasing the most innovative and path-breaking trends in the field of science & technology.

†† The question was actually asked by Shri Abu Asim Azmi on the floor of the House.